इकाई 11 इष्टतम कराधान

संरचना

11.0 उद्देश्य

11.1 विषय प्रवेश

11.2 इष्टतम कराधान प्रणाली

- 11.2.1 कसौटियाँ
- 11.2.2 अभिलक्षण

11.3 इष्टतम वस्तु कराधान

- 11.3.1 रामसे नियम
- 11.3.2 प्रतिलोम लोच नियम
- 11.3.3 सीमाएँ
- 11.3.4 अनुप्रयोग एवं विस्तार

11.4 इष्टतम आय कराधान

- 11.4.1 व्यवहारात्मक अनुक्रियाओं रहित प्रतिमान
- 11.4.2 व्यवहारात्मक अनुक्रियाओं सहित प्रतिमान (मिर्लीस प्रतिमान)
- 11.4.3 सीमाएँ
- 11.4.4 अनुप्रयोग एवं विस्तार

11.5 सार-संक्षेप

11.6 शब्दावली

11.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

11.8 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

11.0 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद, आप इस योग्य होंगे कि :

- किसी 'इष्टतम कराधान प्रणाली' के सारतत्व की रूपरेखा प्रस्तुत कर सकें;
- किसी इष्टतम कराधान प्रणाली की 'कसौटियाँ' एवं 'अभिलक्षण' निरूपित कर सकें;
- कर की समानुपातिक दरें निर्धारित करने हेतु अपने निहितार्थों के साथ 'प्रतिलोम लोच नियम' निर्दिष्ट कर सकें;
- रामसे इष्टतम कर नियम की व्युत्पत्ति कर सकें;
- दर्शा सकें कि इष्टतम कराधान स्तर पर, कुछ विशेष शर्तों के तहत, हतोत्साहन सूचकांक सभी वस्तुओं में एकसमान होने चाहिए;
- इष्टतम कराधान हेतु रामसे नियम की 'सीमाएँ' एवं 'विस्तार' बता सकें;
- व्यवहारात्मक अनुक्रियाओं की उपेक्षा किए जाने की स्थिति में इष्टतम आय कराधान प्रतिमान की सीमाएँ उजागर कर सकें;
- व्यवहारात्मक अनुक्रियाओं पर विचार किए जाते समय मिर्लीसियन इष्टतम आयकर प्रतिमान के परिणामों पर चर्चा कर सकें; तथा
- नीति-निरूपण में अपनी अनुप्रयोज्यता के साथ इष्टतम कराधान हेतु मिर्लीसियन प्राधार की सीमाएँ एवं विस्तार इंगित कर सकें।

11.1 विषय प्रवेश

सरकार राजस्व एकमुश्त कर लागू करके अथवा वस्तु कर अथवा आयकर लगाकर वसूल करती है। उसे कराधान से जुड़े अनेक प्रश्नों के उत्तर खोजने होते हैं, यथा– (i) एक उचित कराधार कैसे तय किया जाए; (ii) वस्तु कर प्रयोग किया जाए अथवा आयकर अथवा दोनों का मिश्रण; (iii) प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करों के बीच संतुलन कैसे लाया जाए; तथा (iv) कर प्रणाली की प्रगामिता कोटि कैसे निश्चित की जाए। मान लीजिए कि सरकार इकाई करों के रूप में विभिन्न वस्तु करों का विकल्प चुनती है। इससे कीमत अनुपात में भिन्नताओं अथवा उपभोग में प्रतिस्थापन की सीमांत दर के कारण उपभोक्ता के अधिमानों में परिवर्तन आ जाएगा। इसी प्रकार, यदि सरकार व्यक्तियों की आय पर कर वसूलने का फैसला करती है तो इससे करोपरांत वेतन दर और उसके द्वारा व्यक्तियों के आय-उपभोग प्रतिमान पर प्रभाव बदल जाएगा। परिणामतः, कार्य और विश्राम के बीच इष्टतम विकल्प विकृत हो जाता है जिससे उनकी कल्याण हानि हो जाती है। इस प्रकार की निवल हानियाँ सामान्य कर के अत्यधिक बोझ (यथा, अतिरिक्त भार) की ओर प्रवृत्त करती हैं। दक्षता परिप्रेक्ष्य से, लोक-राजस्व में कोई भी वृद्धि एक अपेक्षाकृत लोचहीन विस्तृत आधार पर कर की किसी निम्न दर के माध्यम से लाई जाती है। इस कार्य को इस प्रकार निष्पादित किए जाने की आवश्यकता होती है कि एक ही वस्तु पर बहुविध कराधान से बचा जा सके। समता परिप्रेक्ष्य से, एकत्र राजस्व अल्पतम सुनम्य कर आधार से प्राप्त किए जाने चाहिए। सरकार विभिन्न साधनों वाले सभी करदाताओं (ऊर्द्धव समता) अथवा एकसमान साधनों वाले सभी करदाताओं (क्षैतिज समता) में दक्षता एवं समता के बीच संतुलन लाने का प्रयास करती है। इससे कर-संग्रहण प्रक्रिया में दक्षता एवं समता के बीच संतुलन-प्रयासों का मुद्दा सामने आता है। इष्टतम कराधान सिद्धांत इन प्रश्नों को एक ऐसा कर-प्राधार तैयार करने का प्रयास करके हल करता है जो समता एवं दक्षता के बीच सर्वोत्तम संतुलन स्थापित होने दे। मानक सिद्धांत यह मानकर चलता है कि एक ऐसी कर-प्रणाली चुनी जानी चाहिए जो कि संरोधों की किसी शृंखला के अधीन सामाजिक क्षेम फलन अधिकतम करे। इष्टतम कर विश्लेषण ऐसी कर-शृंखला निर्धारित करने में मदद करता है जो क्षेम-कल्याण स्तर को अधिकतम करें और साथ ही, राजस्व भी बढ़ाएं।

11.2 इष्टतम कराधान प्रणाली

मान लीजिए कि सरकार किसी एकमुश्त कर के माध्यम से राजस्व वसूली का विकल्प चुनती है (यथा, उनके अभिलक्षणों पर ध्यान दिए बिना ही सभी व्यक्तियों के लिए कोई राशि तय करके)। इससे व्यवहारात्मक प्रतिक्रियाएँ नहीं होगी। विकल्पतः, यदि सरकार व्यक्तियों पर पुरोगामी कर वसूलने का निर्णय लेती है (यथा, उच्चतर-सक्षम व्यक्ति वृहत्तर राशि चुकाएँ), इससे यह प्रकृति में पुनरावंटनकारी बन जाती है, जो कि समता परिप्रेक्ष्य की भूमिका निभाती है। कोई भी पुनरावंटन योजना, व्यक्तियों की अंतर्जात योग्यता पर आधारित, 'प्रथम-सर्वोत्तम योजना' कहलाती है किंतु अंतर्निहित योग्यता को ज्ञात तो स्वयं व्यक्तियों को ही होता है, सरकार को नहीं। चूँकि सरकार लोगों की कमाई का अवलोकन कर सकती है, वह व्यक्तियों की आय पर कर लगाती है। इसे 'द्वितीय-सर्वोत्तम पुनरावंटन योजना' कहा जाता है। किसी भी इष्टतम कर प्रणाली में, सरकार इसलिए कर लगाती है कि राजस्व समाज के विकास पर खर्च किया जा सके। दूसरे शब्दों में, कोई भी इष्टतम कर प्रणाली एक ऐसा पैरेटो-दक्ष कर प्राधार खोजती है जो कि निष्पक्षता अथवा समता संबंधी संरोधों को संतुष्ट करते हुए किसी क्षेम फलन को अधिकतम करें।

11.2.1 कसौटियाँ

जबकि कोई भी राजस्व सृजन प्रणाली किसी संभव कर शृंखला पर निर्भर करती है,

सरकार की समस्या प्रायः कुछ कसौटियों के आधार पर परोक्ष (जैसे– वस्तु अर्थात् उपभोज्य वस्तु) और प्रत्यक्ष (जैसे– आय) कराधान के बीच विकल्प चुनने में निहित होती है। सैण्डमो (1976) ने तीन इष्टतमता कसौटियों की एक शृंखला निम्नवत् प्रस्तुत की :

1) **लागत न्यूनतमीकरण** : किसी भी इष्टतम कर प्रणाली को कर-निर्धारण एवं प्रबंधन में उपगत संसाधन लागत, यथा, कर वसूली पर खर्च धन, समय एवं प्रयासों की दृष्टि से संग्रहण लागत एवं करदाताओं की लागत, न्यूनतम करनी चाहिए।

2) **निष्पक्षता अथवा समता** : यह कर चुकाने की क्षमता, प्रदत्त सेवा लागत एवं प्राप्त लाभ राशि से जुड़े न्याय अथवा निष्पक्षता की कसौटी होती है।

3) **आर्थिक दक्षता** : किसी भी इष्टतम कर प्रणाली को व्यवहारात्मक प्रतिक्रियाओं के कारण विकृतियों की वजह से संभावित न्यूनतम निवल हानि की ओर प्रवृत्त रहना चाहिए।

11.2.2 अभिलक्षण

इष्टतम कराधान प्रतिमानों पर लेख, पुस्तकें आदि निम्नलिखित तीन अभिलक्षण इंगित करते हैं –

1) **राजस्व उगाही हेतु साध्य करों की शृंखला** : प्रत्येक प्रतिमान साध्य करों (वस्तु एवं आय दोनों करों) की एक शृंखला निर्दिष्ट करता है, जो कि सरकार लोक राजस्व का वांछित स्तर बढ़ाने के लिए 'व्यक्तियों एवं फर्मों' पर वसूल कर सकती है। एकमुश्त कर (जिनके लिए कर-देयता आर्थिक दशा से असंबद्ध होती है) आमतौर पर वर्जित होते हैं।

2) **व्यक्तियों एवं फर्मों के अधिमान** : यहाँ, प्रतिमान यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि व्यक्ति एवं फर्में करों के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया देते हैं। उदाहरण के लिए, वस्तुओं एवं विश्राम के विषय में भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न अधिमान दर्शाते हैं। परिणामतः, लोग भिन्न-भिन्न करों के प्रति विभिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं। इसी प्रकार, वस्तु-उत्पादन हेतु किसी प्रदत्त प्रौद्योगिकी के साथ विभिन्न फर्में करों के प्रति विभिन्न रूप से प्रतिक्रिया देती हैं। इन प्रतिमानों में, व्यक्ति एवं फर्में किसी प्रदत्त बाज़ार प्राधार में, प्रायः पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत अंतर्क्रिया करते हैं।

3) **सरकार का वस्तुनिष्ठ फलन** : प्रत्येक प्रतिमान (सरकार के लिए) कर-प्रणाली द्वारा उत्पन्न भार के न्यूनतम करने हेतु करों की भिन्न संस्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ फलन विर्निदिष्ट करता है ताकि दक्षता एवं समता के बीच संतुलन लाया जा सके।

11.3 इष्टतम वस्तु कराधान

सरकार एकमुश्त कर लगाकर अथवा वस्तु कर अथवा आयकर अथवा इनके किसी संयोजन से राजस्व पा सकती है। एकमुश्त कर गैर-विरूपणकारी होता है, वस्तु कर उत्पादक कीमत एवं उपभोक्ता कीमत के बीच अंतर उत्पन्न कर अर्थव्यवस्था में विकृतियाँ ला देता है। साथ ही, लगाए गए कर उत्पादनकर्ता की लागत बढ़ाकर उन्हें प्रभावित करते हैं। इस प्रकार की विकृतियाँ प्रणाली में अदक्षता (निवल हानि) उत्प्रेरित कर कल्याण-हानि में परिणत होती हैं। इस भाग में, हम यह पता लगाएंगे कि वस्तु कर किस प्रकार समता एवं दक्षता संबंधी सरोकारों के आधार पर इष्टतम रूप से अभिकल्पिक किए जा सकते हैं।

11.3.1 रामसे नियम

मान लीजिए कि सरकार वस्तु करों की कोई शृंखला लागू कर एक निश्चित राजस्व

राशि को बढ़ाना चाहती है। एक स्वाभाविक प्रश्न होगा : वस्तु कर दरों का कौन-सा विकल्प (अथवा संयोजन) राजस्व की इष्टतम राशि उत्पन्न करते समय समाज की क्षेम-हानि को न्यूनतम करेगा? दूसरे शब्दों में, हम तय करना चाहेंगे कि क्या एक समान पण्य (वस्तु एवं सेवा) कर दरें इष्टतम होंगी? इसे ही दक्ष कराधान की रामसे समस्या कहा जाता है। अपने सरलतम रूप में, रामसे (1927) द्वारा प्रस्तावित प्रतिमान किसी भी सजातीय जनसमुदाय हेतु एक स्थायी प्रतिमान है। सरकार का मुख्य उद्देश्य कर-प्रणाली द्वारा उत्पन्न अत्यधिक बोझ को कम करते हुए राजस्व की नियत राशि को बाह्यजात रूप से बढ़ाना माना जाता है। माना जाता है कि यह वेतन आय पर कोई कर नहीं लगाती। विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं पर कोई एकसमान दर कर वसूला जाता है। सरकार से दो उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कर तय करने की अपेक्षा की जाती है, यथा– (i) नियत कुल राजस्व (R) बाह्यजात रूप से बढ़ाना, तथा (ii) व्यक्तियों की उपयोगिता हानि न्यूनतम करना (यथा, कराधान का अतिरिक्त भार न्यूनतम करना)। दूसरे शब्दों में, इन अवधारणाओं का अर्थ है – (i) कोई एकमुश्त कराधान होगा; (ii)) सभी जिंसों पर कर नहीं लगाया जा सकता (यथा, विश्राम पर कर नहीं लगता); तथा (iii) उत्पादक कीमतें p_i नियत होती हैं। तद्नुसार, उपभोक्ता कीमतें q_i = उत्पादक कीमतें, p_i + कर τ_i. सरलीकरण की दृष्टि से, उत्पादक कीमत एक पर सामान्यीकृत किए जाते हैं, यथा p_i = 1. तद्नुसार $q_i = 1 + \tau_i$.अपने स्थायी रूप (यथा, बिना बचत के एक-अवधि प्रतिमान) में, किसी एकल प्रतिनिधि उपभोक्ता की कल्पना की जाती है ताकि वह व्यक्ति कर के प्रभाव को आंतरीकृत न कर सकें (व्यक्ति किसी भी वृहद् अर्थव्यवस्था की एक लघु सत्ता होता है)। इसका अर्थ यह मान लेना है कि यहाँ कोई समता अथवा पुनर्वितरण सरोकार नहीं होते। N वस्तुओं एवं l श्रमिकों के साथ वैयक्तिक उपभोक्ता कुल आय (Y) (वेतन एवं गैर-वेतन दोनों स्रोतों से) से कम अथवा उसके बराबर पर नियंत्रित बजट संरोधों [यथा, कुल व्यय (E)] के अधीन उपयोगिता $u(x_1, x_2, \ldots . x_N, l)$ को अधिकतम कर सकता है। E उपभोक्ता कीमतों के वस्तु मात्राओं से गुणनफलों का कुल योग है, यथा $E = q_1x_1 + q_2x_2 + \cdots + q_Nx_N = \sum_{i=1}^{N} q_ix_i$ कुल वेतन आय (W) वेतन दर (w) गुणा श्रमिक संख्या l होती है, यथा : $W = wl$. यदि कुल गैर-वेतन आय Z हो तो $Y = wl + Z$. चूँकि वेतन आय पर कोई कर नहीं लगाया गया है, हल की जाने वाली समस्या बजट के अधीन अपनी उपयोगिता फलन $u(x_1, x_2, \ldots . x_N, l)$ अधिकतम करने वाले उपभोक्ता से जुड़ी है, यथा–$\sum_{i=1}^{N} q_ix_i \leq wl + Z$. इस अधिकतमीकरण समस्या हेतु लैग्रेंजियन होगा –

$$L_c = u(x_1, x_2, \ldots . x_N, l) + \alpha[wl + Z - \sum_{i=1}^{N} q_ix_i] \qquad (11.1)$$

प्रथम-कोटि शर्त (FOCs) के अनुसार,

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = 0 \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x_i} = u_{x_i} = \alpha q_i \qquad (11.2)$$

यदि v कोई निश्चित उपयोगिता हासिल करने हेतु किसी व्यक्ति द्वारा खर्च धन का मान हो तो $\alpha = \frac{\partial V}{\partial Z}$ उपभोक्ता के लिए धन का सीमांत मान अथवा वेतन की सीमांत उपयोगिता होगी। इससे माँग फलन $x_i(q, Z)$ के रूप में और परोक्ष उपयोगिता फलन $V(q, Z)$ के रूप में प्राप्त होता है, जहाँ $q = (w, q_1, q_2, \ldots . , q_N)$. वस्तुनिष्ठ फलन है। अतएव, राजस्व संरोध के अधीन $\max V(q, Z)$ हेतु हल करना होगा, जो कि निम्न प्रकार से दर्शाया जाएगा –

$$\tau . x = \sum_{i=1}^{N} \tau_i x_i(q, Z) \geq R \qquad (11.3)$$

समतुल्य रूप से, सरकार कराधान का अतिरिक्त भार (EB) न्यूनतम करती है जिसके लिए प्रतिनिर्मेय होगा– राजस्व निबाध (11.3) के अधीन $\min EB(q) = e(q, V(q, Z)) - e\big(p, V(q, Z)\big) - R$ यथा $\tau . x = \sum_{i=1}^{N} \tau_i x_i(q, Z) \geq$

R। ध्यान दें कि $e(q, V(q, Z))$ $V(q, Z)$ में निरंतर से बढ़ रहा है और R व Z नियतांक हैं। चूंकि अधिकतमकारी $V(q, Z)$ न्यूनतमकारी $-e(p, V(q, Z))$ के समान ही है, कराधान का अतिरिक्त भार कारारोपण की विद्यमानता में उपयोगिता स्तर $V(q, Z)$ को बनाए रखने के रूप में आकलित किया जाता है। इसका लैग्रेंजियन होगा –

$$L_G = V(q, Z) + \lambda[\sum_{i=1}^{N} \tau_i x_i(q, Z) - R] \tag{11.4}$$

अतः, $\frac{\partial L_G}{\partial q_i} = \frac{\partial V}{\partial q_i} + \lambda\left[x_i + \sum_j \tau_j \, \partial x_j/\partial q_i\right] = 0$ (11.5)

जहाँ, $\frac{\partial V}{\partial q_i}$ उपभोक्ता की क्षेम हानि है, x_i यांत्रिक प्रभाव है और $\sum_j \tau_j \, \partial x_j/\partial q_i$ व्यवहारपरक प्रतिक्रिया हेतु पदबंध है। धन के ऋणात्मक सीमांत मान हेतु रॉय समिका $\frac{\partial V}{\partial q_i} = -\alpha x_i$ का प्रयोग करने पर, समीकरण (11.5) हो जाता है–

$$-\alpha x_i + \lambda\left[x_i + \sum_j \tau_j \, \partial x_j/\partial q_i\right] = 0$$

$$\Rightarrow (\lambda - \alpha)x_i + \lambda \sum_j \tau_j \, \partial x_j/\partial q_i = 0 \tag{11.6}$$

$$\Rightarrow \sum_j \tau_j \, \partial x_j/\partial q_i = \frac{-x_i}{\lambda}(\lambda - \alpha) \tag{11.7}$$

समीकरण (11.7) का अर्थ है कि इष्टतम कर दर को N अज्ञात व्यक्तियों के साथ N समीकरणों के किसी तंत्र को संतुष्ट करना ही चाहिए। यथा i = 1, 2, ……., N हेतु। समीकरण (11.7) ही 'रामसे इष्टतम कर नियम' है, जिसका अर्थ होता है– केवल एक ही जिंस या पण्य पर कर नहीं लगाया जा सकता (चूँकि $\partial x_j/\partial q_i = \partial x_j/\partial \tau_i$), तद्नुसार, स्लट्स्की समीकरण से हमें प्राप्त होता है :

$$\partial x_j/\partial q_i = \partial h_j/\partial q_i - x_i \, \partial x_j/\partial Z \tag{11.8}$$

समीकरण (11.8) को समीकरण (11.7) में प्रतिस्थापित कर हमें प्राप्त होगा –

$$\sum_j \tau_j \left[\partial h_j/\partial q_i - x_i \, \partial x_j/\partial Z\right] = \frac{-x_i}{\lambda}(\lambda - \alpha) \tag{11.9}$$

समीकरण (11.9) 'रामसे इष्टतम कर सूत्र' के 'प्रतिपूर्तित लोच निरूपण' हेतु निम्न सूत्र देता है –

$$\frac{1}{x_i}\sum_j \tau_j \, \partial h_i/\partial q_j = \frac{-\theta}{\lambda} \tag{11.10}$$

जहाँ, $\theta = \lambda - \alpha - \lambda \frac{\partial}{\partial Z}\sum_j \tau_j x_j$ स्वयं i से स्वतंत्र है और एकमुश्त कर की एक इकाई लागू करने हेतु सरकार के लिए मान का परिमापन करता है। सहज रूप से, θ धनात्मक होना चाहिए क्योंकि सरकार एकमुश्त कर लगाने का सकारात्मक प्रभाव ही देखना पसंद करेगी। $\sum_j \tau_j \, \partial h_i/\partial q_j$ कर दरों τ_j द्वारा गुणित हिक्सीयन लोचों $\partial h_i/\partial q_j$ का भारित कुल योग है। तीन पद λ, α और $\frac{\partial}{\partial Z}\sum_j \tau_j x_j$ एकमुश्त कर की 1 इकाई लागू करने के तीन विभिन्न प्रभाव निरूपित करते हैं। चर λ (सरकारी बजट संरोध का लैग्रेंजियन का गुणक) व्यक्ति के लिए क्षेम-हानि है और $\frac{\partial}{\partial Z}\sum_j \tau_j x_j$ व्यवहारपरक प्रभाव के कारण राजस्व में हानि है।

यदि सरकारी राजस्व आवश्यकता (R) अल्प हो, जिससे सभी कर भी अल्प ही होंगे, तो वस्तु j पर कर τ_j वस्तु i का उपभोग (उपयोगिता स्थिर रखते हुए) लगभग $dh_i = \tau_j \partial h_i/\partial q_j$ तक घटा देगा, जहाँ $\partial h_i/\partial q_j$ वस्तु j के संबंध में वस्तु i हेतु माँग की हिक्सीयन प्रतिलोच है (यथा, जब वस्तु j पर कर 1% तक बढ़ाया जाता है तो

वस्तु i हेतु माँग में कितना परिवर्तन आएगा, बशर्ते उपयोगिता नियतांक $\partial h_i/\partial q_j$) से दर्शायी गया हों)। तद्नुसार, $\sum_j \tau_j \partial h_i/\partial q_j$ सभी करों के कारण उपयोगिता स्थिर रखते हुए वस्तु i के उपभोग में कुल गिरावट को निरूपित करता है। समीकरण (11.10) का बायाँ पक्ष, यथा $\frac{1}{x_i}\sum_j \tau_j \partial h_i/\partial q_j$ की व्याख्या 'वस्तु 'i" के उपभोग में प्रतिशत गिरावट' के रूप में की जा सकती है, यथा– वस्तु i पर कर प्रणाली के 'हतोत्साहन का सूचकांक'। समीकरण (11.10) का दायाँ पक्ष, यथा, $\frac{\theta}{\lambda}$ स्थिर रहता है। इस प्रकार, रामसे सूत्र बतलाता है कि इष्टतम अवस्था में सभी वस्तुओं के 'हतोत्साहन के सूचकांक एकसमान ही होने चाहिए'।

11.3.2 प्रतिलोम लोच नियम

समीकरण (11.10) में हिक्सीयन माँगों ϵ_{ij}^c से क्षतिपूर्ति लोच हेतु पद का प्रयोग कर उसे $q_j = 1 + \tau_j$ से गुणा व भाग कर हम रामसे सूत्र को पुनः निम्नवत् लिख सकते हैं:

$$\sum_{j=1}^{N} \frac{\tau_j}{1+\tau_j} \epsilon_{ij}^c = \frac{\theta}{\lambda} \qquad (11.11)$$

समीकरण (11.11) ही प्रतिलोम लोच नियम है। एक विशेष उदाहरण स्वरूप, जब हम यह मानकर चलते हैं कि स्लस्ट्की आव्यूह विकर्णी है (अर्थात् सभी प्रतिलोच $\varepsilon_{ij} = 0\ i$ यदि $i \neq j$) तो हमें प्राप्त होता है :

$$\frac{\tau_j}{1+\tau_j} = \frac{\theta}{\lambda} \cdot \frac{1}{\varepsilon_{ii}} \qquad (11.12)$$

समीकरण (11.12) ही श्रेष्ठ 'प्रतिलोम लोच नियम' है। इस नियम के अनुसार, वस्तु i पर कर की समानुपाती दर माँग संबंधी उसकी कीमत लोच से विलोमतः संबद्ध होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, रामसे नियम माँग की क्षतिपूर्तित लोचों के विपरीत अनुपात में विभिन्न कर आधारों पर कर लगाने के पक्ष में है। इसका अर्थ है कि अधिक लोचदार वस्तुओं पर अपेक्षाकृत कम कर होने चाहिए ताकि सरकार द्वारा राजस्व सृजन को इष्टतम किया जा सके।

11.3.3 सीमाएँ

जबकि एकरूप वस्तु कर संबंधी अवधारणा विभिन्न वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में विकृतियों पर अंकुश रखती है, अपनी अंतर्निहित अवधारणाओं के कारण रामसे प्रतिमान की आलोचनाएँ निर्णय सामने आई हैं [जैसे, सभी जिंसों पर कर नहीं लगाया जाता और आपूर्ति वक्र पूर्णतः लोचदार (निहित अवधारणा) जिससे करों संबंधी भार आयतन उपभोक्ता ही सहन करते हैं]। व्यावहारिकता की दृष्टि से, रामसे सूत्र सरकार से यह सिफारिश करता है कि वह गैर-लोचदार वस्तुओं पर अधिक कर लगाए अथवा उन वस्तुओं पर करभार अधिक डाले जहाँ निवल हानि कम हो। जबकि इसका उद्देश्य दक्षता लागतें न्यूनतम करना होगा, सरकार माँग की कम लोच दर्शाने वाली अनिवार्य वस्तुओं पर अधिक कर लगाए। आवश्यक वस्तुओं पर अधिक कर लगाने के फलस्वरूप, निम्न-आय उपभोक्ताओं को उच्च-आय उपभोक्ताओं की अपेक्षा कहीं अधिक कर चुकाना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि उस गरीब पर जो आमतौर पर अधिक अनिवार्य वस्तुओं का उपभोग करता है, उस अमीर से, जो आमतौर पर अनिवार्य वस्तुओं का उपभोग गरीब से कम करता है, अधिक कर लगेगा। विलास वस्तुओं पर करों के लिए उक्त का विलोम होगा। इस अर्थ में, करारोपण गैर-समतावादी होगा। अतएव, रामसे समाधान जिंसों पर कर लगाने का एक दक्ष तरीका तो बताता है मगर किसी न्यायोचित विधि से नहीं। रामसे प्रतिमान एक प्रतिगामी इष्टतम कर प्रणाली सुझाता है। तद्नुसार, जबकि 'क्या किसी एकसमान दर से सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर लगाए' संबंधी मूल रामसे समस्या इष्टतम शेष (यथा, पूर्णतः उत्तरित नहीं) ही है, रामसे समाधान कम से कम यह तो सुझाता ही है कि एकसमान दरें प्रायः इष्टतम हासिल नहीं करतीं।

11.3.4 अनुप्रयोग एवं विस्तार

कॉर्लेट एवं हेग (1953) बताते हैं कि विभिन्न वस्तुओं पर इष्टतम कर दरें वस्तु हेतु माँग और विश्राम के बीच संबंध पर निर्भर करती हैं। रामसे प्रतिमान विश्राम के संपूरकों पर उच्चतर कर दरों और श्रम के संपूरकों पर निम्नतर कर दरों वाले वस्तु करों की एक इष्टतम संस्थिति प्रदान करता है। इस व्याख्या के पीछे सहज बोध यही है कि चूँकि विश्राम एक कर रहित वस्तु है, विश्राम की संपूरक वस्तुओं पर कर लगाना अव्यक्त रूप से विश्राम पर भी कर लगाता है। तद्नुसार, विश्राम को एक ऐसी वस्तु माना जाता है जिसकी लिए कीमत ही उसकी अवसर लागत होगी (कार्यकाल की तुलना में विश्राम काल के कारण उपभोग की हानि की दृष्टि से)। रामसे नियम सुझाता है कि वे मदें जो विश्राम की निकट प्रतिस्थापी हों, उन पर कम कर लगाया जाना चाहिए। यदि चालू उपभोग बचत की बजाय विश्राम का एक निकटतर प्रतिस्थापी हो तो सरकार से चालू उपभोग की बजाय बचत पर अधिक कर लगाए जाने की सिफारिश की जाए (चूँकि कर को विश्राम का एक निकट प्रतिस्थापी के रूप में लिया जा सकता है)। एक अन्य अनुप्रयोग व्यक्तिगत सेवा क्षेत्रों पर कर लगाने में है; जैसे बाग़वानी, बच्चों की देखभाल अथवा प्रतिस्थापी है। रामसे नियम स्पष्ट करता है कि कार्य के अधिक घंटों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यक्तिगत सेवाओं पर निम्नतर कर लगाया जाना चाहिए।

रामसे प्रतिमान के अनेक विस्तार देखने में आते हैं। डायमंड (1975) ने लैग्रेंज गुणक λ के स्थान पर विशिष्ट वस्तुओं के उपभोक्ताओं के लिए औसत सीमांत उपयोगिता को रखकर उक्त प्रतिमान को विस्तार दिया। ऐसा करके, रामसे प्रतिमान के पुनराबंटनकारी सरोकारों पर विचार उसमें समता को समाविष्ट करने हेतु विभिन्न अधिमानों (रुचियों) वाले परिवारों पर विचार करके किया जाता है। डायमंड प्रतिमान में, सरकार का सामाजिक कल्याण फलन वैयक्तिक उपभोक्ताओं की उपयोगिताओं का एक भारित औसत होता है। परिवारों के लिए सामाजिक क्षेम भार की सटीक विस्तृति परिवार की स्वस्थता पर निर्भर करती है [अल्प-लाभांवित (निर्धनतर) परिवारों को उच्चतर भार दिया जाता है]। डायमंड प्रतिमान, तद्नुसार, निर्धन वर्ग द्वारा प्रमुखता से प्रयुक्त आवश्यक वस्तुओं की अपेक्षा विलास-वस्तुओं पर कहीं अधिक कर लगाकर इष्टतम वस्तु कर प्रणाली में समता का समावेश करता है। उदाहरण के लिए, हम जानते हैं कि निर्धन वर्ग किराने पर धनवान वर्ग की अपेक्षा अपने व्यय का कहीं अधिक भाग खर्च करता है। इन मदों पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) कर-प्रणाली में समतापूर्णता ला देता है। बहरहाल, यह विधि मूल रामसे नियम का अनुसरण करने में विफल रहती है क्योंकि किराना हेतु माँग अपेक्षित रूप से लोचहीन होती है।

बोध प्रश्न 1 (दिए गए स्थान में अपना उत्तर लगभग 50–100 शब्दों में लिखें।)

1) वे मूल सरोकार क्या हैं जिन पर इष्टतम कराधान सिद्धांत विचार करने का प्रयास करता है? कैसे?

.....

.....

.....

.....

.....

2) 'द्वितीय सर्वोत्तम पुनरावंटन योजना से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

3) रामसे नियम का सार क्या है? इसका मूल स्वभाव बताएँ? वे अवधारणाएँ क्या हैं जो कि रामसे द्वारा प्रस्तावित नियम प्रस्तुत करती हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

4) रामसे के इष्टतम कर नियम हेतु पदबंध लिखें। इस नियम का क्या निहितार्थ है? 'क्षतिपूर्तित लोच निरूपण' हेतु पदबंध किस प्रकार सरकार के लिए एकसमान वस्तु कर का निहितार्थ जानने में सहायक सिद्ध होता है?

.....

.....

.....

.....

.....

5) 'प्रतिलोम लोच नियम' किस प्रकार उपयोगी सिद्ध होता है?

.....

.....

.....

.....

.....

6) रामसे कर नियम की सीमाएँ बताइए।

.....

.....

.....

.....

7) डायमंड की व्याख्या रामसे की व्याख्या से किस प्रकार बेहतर है?

.....

.....

.....

.....

.....

11.4 इष्टतम आय कराधान

इष्टतम आय कर नियमों में मूल समस्या आती है– समता और दक्षता के बीच संतुलन-प्रयास कैसे न्यूनतम किए जाएँ? तद्नुसार, जबकि आयकर को पुनर्वंटनकारी लक्ष्य हासिल करने हेतु आवश्यक माना जाता है, पुनर्वंटनकारी सरोकार, उच्चतर आयकर दरें अदक्षता लागतों को अध्यारोपित करते हैं। अदक्षता लागतों के तीन मुख्य स्रोत हैं– (i) वस्तु क्षेत्र में उत्पन्न विकृतियों के कारण निवल हानि, (ii) कर-संग्रह की प्रशासी लागतें, और (iii) कर कानूनों की अनुपालन लागतें। आय के कराधान से यह प्रश्न उठता है कि केवल अर्जित आय पर ही कर लगाया जाए अथवा 'पूर्ण संभावित आय' पर कर लगाया जाए? जेम्स मिर्लीस (1971) ने अपने इष्टतम अर्जित आय कराधान प्रतिमान में एक स्थिर सामाजिक क्षेम प्राधार में श्रमिक बाज़ार में दृष्टिगत व्यवहारात्मक अनुक्रिया को शामिल किया है। इस भाग में, हम दो इष्टतम आय कराधान प्रतिमानों पर विचार करेंगे– (i) व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं रहित (निर्देश-चिह्न), और (ii) व्यवहारात्मक प्रतिक्रियाओं सहित। किंतु उससे पहले हम कुछ मूल संकल्पनाओं से परिचित हो लें।

इष्टतम आय कराधान के दो प्रकार के स्थिर प्रतिमान देखे जाते हैं– रैखिक और अरैखिक। इष्टतम वस्तु कराधान विषयक लेख, पुस्तकें आदि रैखिक कर-प्रणालियों की ओर व्यावर्तित होते हैं और इष्टतम आय कराधान अरैखिक कर-प्रणालियों की ओर। रैखिक आय कर-प्रणालियों के दो प्राचल देखे जाते हैं। एक जन-अनुदान (किसी अनुदान की भाँति अनार्जित आय) और दूसरा, कोई सीमांत कर दर। हम यह मानकर चलते हैं कि $T(z)$ कर देयता को इंगित करता है, यथा, अर्जित राशियों का कोई फलन z, जिससे $-T(z)$ अर्जित आय z पर हस्तांतरण लाभ दर्शाएगा। शून्य अर्जित राशियों वाले हस्तांतरण लाभ का आकार होगा : $-T(0) \geq 0$. यह हस्तांतरण लाभ (यथा, शून्य अर्जित राशियों वाला हस्तांतरण लाभ) ही है जो *जन-अनुदान* कहलाता है। यह जनानुदान प्रत्येक व्यक्ति के लिए किसी एकमुश्त अनुदान (प्रत्याभूत आय) के रूप में हो सकता है अथवा किसी एकमुश्त कर के रूप में। रैखिक कर परिदृश्य में, किसी ज्ञात आय पर कर-देयता एकमुश्त अनुदान की राशि होगी और किसी नियत कर दर τ वाली उस आय पर चुकाया गया कुल कर; यथा, $T(z) = -T(0) + \tau z$,जहाँ $T(0) \leq 0$ और $0 < \tau < 1$ । तद्नुसार, आय कर के पश्चात् निवल आय होगी– $z - T(z) = -T(0) + (1 - \tau)z$. सीमांत कर दर आय में परिवर्तनों के कारण देयता में परिवर्तन ही है, यथा, $T'(z) = \tau$ (नियतांक)। आय पर सीमांत कर दर श्रम आपूर्ति निर्णय को विकृत कर देती है और इस प्रकार एक दक्षता लागत दर्शाती है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति अर्जित राशियों की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए $1 - T'(z)$ रख लिया करते हैं। यह संकल्पना गहन सीमांत आय-आपूर्ति से उत्पन्न प्रतिक्रियाएँ मापने हेतु प्रासंगिक होती है, जो कि भागीदार श्रमिकों के बीच कार्य करने में व्यतीत घंटों की वास्तविक संख्या मापती है।

किसी जनानुदान और किसी सीमांत कर दर का विकल्प चुनकर सरकार राजस्व बढ़ा सकती है और विभिन्न आय-संग्रहों के बीच आय पुनरावंटित कर सकती है। तद्नुसार, इन प्राचलों का इष्टतम विकल्प चुना जाना इन बातों पर निर्भर करेगा – (क) सरकार को लोक राजस्व की आवश्यकता है; (ख) पुनरावंटन हेतु समाज के अधिमान (किसी समाज-कल्याण फलन के माध्यम से प्रदर्शित); (ग) करोपरांत वेतन के संबंध में व्यक्तियों की श्रम-आपूर्ति संबंधी लोच; और (घ) अर्थव्यवस्था में कर पूर्व वेतन आय की असमानता का वितरण। अरैखिक आयकर प्रणालियाँ उत्पन्न आर्थिक विकृतियों को न्यूनतम करते हुए आय स्तर के साथ सीमांत कर दर में निरंतर परिवर्तन होने देती हैं (उदाहरणार्थ,

शून्येतर सीमांत कर दरों द्वारा और समता सरोकारों हेतु कारण देकर)। अवधारणा यह है कि विभिन्न कौशलों अथवा अंतर्जात क्षमताओं के कारण, सरकार व्यक्तियों के विविध उत्पादकता स्तरों का अवलोकन नहीं कर सकती। यदि ऐसा करना संभव होता तो सरकार कार्य-क्षमता के आधार पर गैर-विरूपणकारी व्यक्ति-विशेष कर वसूल सकती थी। अतएव, उत्पादकता पर कर लगाने के परोक्षी स्वरूप, सरकार आय पर कर लगा देती है। बहरहाल, यदि आयकर अनुचित रूप से अधिक हो तो कुछ व्यक्ति कराधान से बचने के लिए परिश्रम के प्रति हतोत्साहित होंगे। इसी पृष्ठभूमि में अब हम ऊपर बताए गए दो प्रकार के प्रतिमानों पर विचार करेंगे।

11.4.1 व्यवहारात्मक अनुक्रियाओं रहित प्रतिमान

यहाँ, इस प्रतिमान में, सभी व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एकसमान वर्धमान एवं नतोदर उपयोगिता $u(c)$ दर्शाते हैं, जहाँ उपभोग c करोपरांत आय है। आय z को इस प्रकार एक घनत्व फलन $h(z)$ के साथ आवंटित माना जाता है कि z प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियत और एकसमान होता है। यदि $T(z)$ आय z पर कर हो तो $c = z - T(z)$. इन अवधारणाओं के तहत, किसी ज्ञात राजस्व आवश्यकता (R) हेतु, उपयोगितावादी सरकार के समक्ष इसके प्रयोजन (जो कि सभी व्यक्तियों की उपयोगिताओं का योग होगा) को अधिकतम करने का प्रश्न होगा, जो कि निम्नवत् है–

$$\int_0^\infty u\big(z - T(z)\big)h(z)dz \qquad (11.13)$$

बजट संरोध $\int T(z)h(z)dz \geq R$ के अधीन।

सरलीकरण हेतु समाकल चिह्न का विलोप कर लैग्रेंजियन निम्नवत् लिखा जाएगा :

$$L\big[u\big(z - T(z)\big) + \lambda\, T(z)\big]h(z) \qquad (11.14)$$

प्रथम-कोटि शर्त से प्राप्त होगा

$$\frac{\partial L}{\partial T(z)} = \big[-u'\big(z - T(z)\big) + \lambda\big]h(z) = 0$$

$\Longrightarrow u'\big(z - T(z)\big) = \lambda \Longrightarrow z - T(z) = c$ (सभी z हेतु नियतांक)

$\Longrightarrow c = \bar{z} - R,$ जहाँ $\bar{z} = \int zh(z)dz$ ही औसत आय है।

परंतु यथार्थ प्रश्न है – करोपरांत आय को समीकृत कैसे करें? इससे अनेक समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं। बाह्यजात आय संबंधी अयथार्थपरक अवधारणा से परे, करोपरांत आय का पूर्ण समकरण 100 प्रतिशत सीमांत कर दर आवश्यक कर देगा, जो कि कार्यार्थ सभी प्रोत्साहन ध्वस्त कर देगा।

11.4.2 व्यवहारात्मक अनुक्रियाओं सहित प्रतिमान (मिर्लीस मॉडल)

यह ज्ञात होने पर कि व्यक्ति आय अर्जित करने की भिन्न-भिन्न क्षमताएँ रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों का सातत्यक दृष्टिगत होता है जो घनत्व $f\,(w)$ के साथ वितरित उत्पादकता वेतन w में भिन्नता दर्शाते हैं। द्वितीय, कल्याण प्रमेय के अनुसार, किसी भी प्रतिस्पर्धात्मक संतुलन में, कोई भी पैरेटो-दक्ष आवंटन तब तक हासिल किया जा सकता है जब तक कि आरंभिक अक्षयनिधि का कोई उपयुक्त पुनरावंटन (वैयक्तिकीकृत एकमुश्त करों के माध्यम से) प्राप्त किया जा सकता हो। बहरहाल, सूचना विषमता के कारण सरकार ऐसा नहीं कर सकती। इसीलिए वह अवलोकनों (यथा, आय एवं उपभोग) के आधार पर विरूपणकारी कर एवं हस्तांतरण प्रयोग करती है। ऐसा करते समय वह समता एवं दक्ष के बीच संतुलन लाने का प्रयास करती रहती है। मानक श्रम-आपूर्ति प्रतिमान में, व्यक्ति उपयोगिता $u(c,l)$ अधिकतम करता है जो कि निम्नलिखित संरोध के अधीन होता है –

$$c = wl - T(wl) \tag{11.15}$$

जहाँ c उपभोग (अथवा करोपरांत आय) है, l श्रम-आपूर्ति है, w वेतन दर है, और $T(wl)$ एक आय-कर-हस्तांतरण अनुसूची है। यहाँ, सरकार वेतन दर का प्रेक्षण नहीं कर सकती है; केवल कुल वेतन आय wl देख सकती है। मिर्लीस (1971) सामाजिक उपयोगिता फलन को वैयक्तिक आय-राशियों के एक ऐसे भारित योगफल के रूप में परिभाषित करते हैं जो समाज के निर्धनतम स्तरों को कहीं अधिक भार मान देता है। सरकार पूर्व उपभोगोपरांत उपयोगिताओं के भारित योगफल को अधिक करती है। यह सामाजिक उपयोगिता फलन दो संरोधों के तहत अधिकतम किया जाता है – एक, संसाधन संरोध (यथा, कर राजस्व संग्रहण के माध्यम से सार्वजनिक आय) और दूसरा, व्यक्तियों के लिए कोई प्रोत्साहन संरोध, जो कि कार्यार्थ प्रोत्साहन पर कराधान के प्रभाव को मान्यता देता है)। सरकार कोई कर अनुसूची $T(.)$ ज्ञात करना चाहती है ताकि सामाजिक क्षेम फलन को अधिकतम किया जा सके; यथा –

$$SWF = \int G\big(u(c,l)\big)f(w)dw \tag{11.16}$$

जो कि निम्नलिखित के अधीन होगा– (i) संसाधन निबाध $\int T(wl)f(w)dw \geq R$, (ii) वैयक्तिक प्रथम-कोटि शर्त $w(1-T')u_c + u_l = 0$ और (iii) G (.) वर्धमान एवं नतोदर है। क्रम-आपूर्ति लोचों के आधार पर एकांगी प्राधार में, समीकरण (11.16) का सामान्य समाधान निम्नवत् स्पष्ट किया जा सकता है– यदि $h(w)$ और $H(w)$ w हेतु क्रमशः घनत्व और बंटन फलन इंगित करते हों तो आय प्राधार $y(w)$ उत्पादकता w के साथ व्यक्तियों की संख्या के एक वर्धमान फलन, $y(w) = \frac{1-H(w)}{wh(w)}$ के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके अलावा, यदि $\varepsilon(w)$ श्रम-आपूर्ति की लोच का कोई वर्धमान फलन (जैसा कि रामसे प्रतिमान में होता है) हो और $g(w)$ व्यक्तियों को सरकार द्वारा आवंटित भार (सामाजिक उपयोगिता फलन में उत्पादकता w के अनुसार) हो तो उत्पादकता w वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इष्टतम सीमांत कर दर $T'(w)$ निम्नवत् दर्शाई जाएगी–

$$\frac{T'(w)}{1-T'(w)} = \varepsilon(w)g(w)y(w) \Rightarrow T'(w) = \frac{\varepsilon(w)g(w)y(w)}{1+\varepsilon(w)g(w)y(w)} \tag{11.17}$$

मिर्लीस (1971) द्वारा सुझाया गया समाधान है– (i) सीमांत कर दर शून्य कर से 100 प्रतिशत कर के बीच ही होनी चाहिए, यथा, आय z पर अथवा $0 \leq T'(z) \leq 1$; और (ii) उच्चतम आय व्यक्ति के लिए सीमांत कर दर शून्य होगी, यथा $T'(.) = 0$, यदि कौशल बंटन की सीमा निश्चित हो। प्रथम परिणाम अर्थात् 'सीमांत कर दर 100 प्रतिशत से कम है' नगण्य है। दूसरा परिणाम अर्थात् 'कराधान की सीमांत दर बहुत अधिक ऊँची न हो यदि उच्चतर उत्पादकता वाले अनेक व्यक्ति विद्यमान हों', इस तर्काधार से सामने आता है कि लोग बजट में महत्त्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं यदि वे कार्य हेतु हतोत्साहित न हों। जब परिबंधित कौशल बंटन वाले किसी उच्चतम आय व्यक्ति के समक्ष शून्य सीमांत कर दर वाली कोई कर अनुसूची हो तो व्यक्ति की करोपरांत आय बढ़ती है। इससे उसे और अधिक कार्य करने हेतु प्रोत्साहन मिलता है। इससे उसका हित लाभ बढ़ता है और सरकार भी उसकी अतिरिक्त आय से राजस्व वसूल सकती है। तद्नुसार, यह समाधान पैरेटो इष्टतम है और यह उचित ठहराता है कि यदि कौशल बंटन परिबंधित हो तो सीमांत कर दर शीर्ष पर शून्य होनी चाहिए। सारतः, पुनरावंटन और दक्षता के बीच इष्टतम आयकर संतुलन प्रयास तल पर एक ऋणात्मक कर (हस्तांतरण) प्रदान करता है और कर अर्जित आय को और बढ़ा देते हैं।

11.4.3 सीमाएँ

हाल के वर्षों में, मिर्लीसियन दृष्टिकोण की अनुप्रयोज्यता पर कुछ प्रगति के बावजूद, कर-नीति अनुप्रयोग के प्रति इसकी जटिलता ने इसे सीमित प्रयोग की वस्तु बना दिया

है। इस अवधारणा के तहत कि हर व्यक्ति की आय उसकी सीमांत उत्पादकता के समान ही होती है, पुनरावंटन में अधिक उत्पादनशील व्यक्तियों पर अधिक कर लगाने की अपेक्षा होती है। तथापि, इस नीति में कर-आधार संकुचित कर देने की प्रवृत्ति देखी जाती है। मिर्लीस परिणाम अपेक्षाकृत निम्न सीमांत दरों वाली किसी स्थूलतः रैखिक इष्टतम कर दर की ओर संकेत करते हैं। यह परिणाम कि इष्टतम कर अनुसूची किसी निश्चित सीमा से ऊपर लगभग रैखिक होती है, तदंतर, अदृढ़ पाया गया (ट्योमाला, 1984)। मिर्लीस के परिणाम की पुष्टि, इसीलिए, उन अवधारणाओं पर निर्भर करती है जो सामाजिक उपयोगिता फलन के संदर्भ में हैं और श्रम-आपूर्ति का लोच सत्य सिद्ध करती हैं।

11.4.4 अनुप्रयोग एवं विस्तार

मिर्लीस प्राधार की दृढ़ता यही है कि यह सरकार को श्रम-आपूर्ति में विकृतियों पर विचार कर सभी व्यवहार्य कर-प्रणालियों पर विचार करने देती है। मिर्लीसियन दृष्टिकोण समता एवं दक्षता के बीच संतुलन-प्रयास से व्युत्पन्न किसी इष्टतम आयकर की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। मिर्लीस प्रतिमान इष्टतम कर प्रगतिशीलता के प्रश्न संबंधी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और बताता है कि कोई भी उपयोगितावादी सामाजिक प्रयोजन फलन, बेशक वह निर्धन वर्ग के कल्याण पर वृहद् भार डालता हो, वह धनाढ्य वर्ग पर उच्च सीमांत कर दरों द्वारा अनिवार्य रूप से अधिकतम नहीं होता। नितांत शीर्ष पर कोई भी शून्येतर सीमांत कर दर, वस्तुतः, निर्धन वर्ग को कम संपन्न बनाती है। हाल के अध्ययनों में मिर्लीस दृष्टिकोण के सामान्य प्रतिपादन प्रदान किए हैं और उसे आनुभविक लेखों, पुस्तकों आदि से जोड़ा गया है। मिर्लीस प्रतिमान के इन रूपों में निम्नतम आय समूह पर उपभोग एवं विश्राम के बीच अपेक्षाकृत निम्न प्रतिस्थाप्यता का समावेश किया है। यह आनुभविक पृष्ठभूमि के साथ एक कहीं अधिक सुसंगत प्राधान प्रदान करता हुआ निम्न-आय व्यक्तियों के लिए उच्चतर सीमांत दरों को उचित ठहराता है।

बोध प्रश्न 2 (दिए गए स्थान में अपना उत्तर लगभग 50–100 शब्दों में लिखें।)

1) 'अदक्षता लागतों' के तीन स्रोत स्पष्ट करें।

.....

.....

.....

.....

.....

2) व्यवहारात्मक अनुक्रियाओं का लेखा-जोखा किए बिना इष्टतम आयकर प्रतिमान की क्या सीमा होती है?

.....

.....

.....

.....

.....

3) क्या आयकर का मिर्लीस समाधान 'पैरेटो इष्टतम' बताया गया है? कैसे?

.....

.....

.....

.....

.....

4) क्या आप मानते हैं कि मिर्लीसियन प्राधार की सीमा जो कि 'व्यवहारतः जटिल' है, सत्य है? इस प्रतिमान अथवा दृष्टिकोण को दृढ़ता से आप क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

11.5 सार-संक्षेप

उन बुनियादी सवालों में से एक, जिनका कि कोई सरकार उत्तर देना चाहती है – अतिरिक्त राजस्व बढ़ाने के लिए करों की कौन-सी स्थिति लागू की जाए ताकि सरकार दक्षता एवं समता कसौटियों पर कोई इष्टतम परिणाम हासिल कर सके? इष्टतम कराधान में उद्देश्य होता है– समता एवं दक्षता हेतु सरोकारों के बीच संतुलन लाना। मिर्लीस (1971) एक अरैखिक स्थिर प्रतिमान के तहत पुरोगामी आयकर की विधि से एक समाधान सुझाते हैं। इस दृष्टिकोण के तहत, सरकार किसी आयकर अनुसूची को इस प्रकार चुनकर किसी उपयोगितावादी सामाजिक क्षेम फलन को अधिकतम करती है कि सीमांत कर दर आय के सभी स्तरों पर शून्य और 100 प्रतिशत के बीच रहे, और कि सीमांत कर दर आय के उच्चतर स्तर पर शून्य रहे। यद्यपि आरंभ के वर्षों में, इसकी जटिलता को नीति में इसके अनुप्रयोग हेतु एक सीमाबद्धता माना जाता था, हाल के वर्षों में, एक इष्टतम आय का संबंध मिर्लीसियन दृष्टिकोण से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसके बावजूद, आमतौर पर, इष्टतम कराधान सिद्धांत की एक आलोचना सामने आती है कि जब यह दक्षता-समता संतुलन-प्रयास की एक बेहतर व्याख्या प्रस्तुत करता है, नीति को क्रियात्मक दिशा-निर्देश प्रदान करने में इसका कार्यक्षेत्र सीमित ही है। जब उपभोग और विश्राम के बीच प्रतिस्थापन की लोच बहुत अधिक हो तो इष्टतम प्रतिमान पुरोगामी कर रूपरेखाएँ प्रदान करने में विफल ही रहते हैं। वे न केवल उच्च रूप से रीतिबद्ध हैं, वरन् कर-संग्रहण की प्रशासी एवं अनुपालन लागतों की भी उपेक्षा करते हैं। इष्टतम कराधान सिद्धांत में भली-भाँति शामिल न किया गया एक अन्य सरोकार प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों करों का प्रयोग करते करों के एक इष्टतम मिश्रण की संस्थिति विषयक है। यह इकाई संक्षेप में इन विषयों के इर्द-गिर्द घटे सैद्धांतिक घटनाक्रम पर एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

11.6 शब्दावली

क्षतिपूर्तित (हिक्सीयन) माँग : किसी वस्तु की उपयोगिता तय करके और उसकी कीमत में परिवर्तन के कारण माँग की अनुक्रियता आकलित करके अवकलित की गई माँग। क्षतिपूर्तित माँग फलन आय प्रभाव को मापे बिना ही कीमत परिवर्तनों के प्रतिस्थापन प्रभाव का प्रग्रहण कर लेते हैं।

इष्टतम कर प्रणाली : वह कर अभिकल्प जो किसी ज्ञात सामाजिक कल्याण फलन को अधिकतम करता हो।

करों की अनुपालन लागत : कानून के अनुसार कर दायित्वों के अनुपालन के साथ उपगत लागतें, यथा विकृतियों के कारण उत्पन्न लागतों के अतिरिक्त कपट एवं कर-परिहार से बचाव की लागतें।

एकमुश्त कर : वह कर भुगतान जिसमें कोई व्यक्ति कोई कार्रवाई करके बदलाव नहीं ला सकता, जिसमें व्यवहारात्मक विकृतियों के कारण शामिल किसी दक्षता लागत का अस्तित्व नहीं रहता। इसे उस समय मुख्य कर कहा जाता है जब कर योग्य राशि करदाताओं के अभिलक्षणों पर ध्यान न देते हुए निर्धारित की जाती है।

अतिरिक्त भार : कराधान के विरूपणकारी स्वभाव के कारण क्षेम हानि की वजह से करदाता की अतिरिक्त लागत।

रॉय की सर्वसमिका : रॉय की सर्वसमिका किसी परोक्ष उपयोगिता फलन से कोई माँग फलन अवकलित किए जाने हेतु साधन प्रदान करती है।

स्लट्स्की समीकरण : यह समीकरण प्रतिस्थापन प्रभाव एवं आय प्रभाव में कीमत-परिवर्तन के कारण माँग में परिवर्तन को विभाजित कर देता है।

पूर्ण संभावना आय : इसका अर्थ है कि वह अधिकतम आय जो कोई कामकाजी व्यक्ति अपना शिक्षा स्तर, अनुभव, कार्यदशाएँ, बाज़ार वेतन-दर आदि ज्ञात होने पर प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकता हो। यह आमतौर पर वास्तविक अर्जित आय से भिन्न होती है।

11.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1) Atkinson A. B. and J. E. Stiglitz (1980). *Lectures on Public Economics*, New York: McGraw-Hill.

2) Kaplow L (2008). *The theory of taxation and public economics*. Princeton: Princeton University Press.

3) Hindriks J. and Gareth D. Myles (2013). *Intermediate Public Economics*, 2nd Edition, MIT Press.

4) Stiglitz, J.E. (2009). *Economics of the Public Sector*, 3rd edition, W.W. Norton and Co.

11.8 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

बोध प्रश्न 1

1) यह 'निवल हानि' को न्यूनतम रखते हुए दक्षता एवं समता सरोकारों के बीच संतुलन रखने का प्रयास करता है। यह ऐसे करों की शृंखला बनाने का प्रयास

करता है जो दक्षता एवं समता के बीच इष्टतम संतुलन प्रयास कर क्षेम-हानि को न्यूनतम करने और राजस्व सृजन का स्तर अधिकतम करें।

2) यह व्यक्तियों की अंतर्जात क्षमता है जो किसी भी आय को अर्जित करने में मदद करती है। परंतु यह सरकार को ज्ञात नहीं होती अथवा उसे सुलभ नहीं होती। अतः, व्यक्तियों द्वारा अर्जित आय, जिसका प्रेक्षण किया जा सकता है, पर कर लगाया जाता है। इसे ही 'द्वितीय सर्वोत्तम' विकल्प कहा जाता है। चूँकि, करों का प्रयोजन संसाधनों का लाभ पुनरावंटित करना होता है, इसे 'द्वितीय सर्वोत्तम पुनरावंटन योजना भी कहते हैं।

3) यह इस बात का अन्वेषण करता है कि क्या कोई एकसमान वस्तु कर इष्टतम हो सकता है? यह एक स्थानीय प्रतिमान है जो समजातीय जनसमुदाय और शून्य वेतन कर की कल्पना करता है।

4) समीकरण (11.7). इसका अर्थ है कि केवल एक जिंस पर ही कर नहीं लगाया जा सकता और प्रतिस्थापन हेतु हतोत्साहन सूचकांक सभी वस्तुओं में एकसमान ही होने चाहिए। $\frac{1}{x_i}\sum_j \tau_j \partial h_i/\partial q_j = \frac{-\theta}{\lambda}$ जहाँ $\theta = \lambda - \alpha - \lambda\frac{\partial}{\partial Z}\sum_j \tau_j x_j$. इसका अर्थ है कि एकमुश्त कर की 1 इकाई लागू कर तीन प्रभावों विषयक कोई भी अवधारणा (यथा, बजट पर गुणक प्रभाव, उपभोक्ता को क्षेम-हानि और व्यवहारात्मक प्रभाव के कारण राजस्व-हानि), जो कि नीति प्रतिपुष्टि हेतु जानना आवश्यक होता है, सरकार के लिए उजागर की जाती है।

5) यह बताते हुए कि 'वस्तु i पर कर की आनुपातिक कर दर माँग संबंधी अपनी कीमत लोच से विलोमतः संबद्ध होनी चाहिए, यह नियम कहता है कि इष्टतम राजस्व सृजन के लिए अधिक लोचदार वस्तुओं पर अपेक्षाकृत कम कर लगाने चाहिए।

6) इसको असमतावादी कहकर इसकी आलोचना की जाती है; यथा, इसमें समता सरोकारों पर यथोचित ध्यान नहीं दिया जाता है।

7) इसके अंतर्गत इष्टतम वस्तु कर प्रणाली में समता का समावेश किया जाता है (निर्धन वर्ग द्वारा प्रमुखतः प्रयोग की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं की अपेक्षा विलास-वस्तुओं पर उच्चतर कर लगाकर)।

बोध प्रश्न 2

1) कर कानूनों का पालन करने में निवल हानि, प्रशासी लागतें और अनुपालन लागतें।

2) 100 प्रतिशत सीमांत कर दर हेतु करोपरांत आय माँगों का समीकरण, जो कि कार्यार्थ सभी प्रोत्साहनों को ध्वस्त कर सकता है।

3) उच्चतर आय-राशियों एवं परिबद्ध कौशलों वाले लोगों के लिए शून्य सीमांत कर दर वाली एक कर अनुसूची की सलाह देकर यह सुझाव पहले से अधिक कार्य किए जाने और अतिरिक्त अर्जित आय से लाभ की संभावना पेश करता है। इस अर्थ में कि सरकार अपेक्षाकृत अधिक राजस्व प्राप्त कर सकती है जो कि लोक सेवाओं पर खर्च किया जा सकता है, यह पैरेटो इष्टतम है।

4) नहीं, वस्तुतः नहीं। यद्यपि कुशल कर्मचारियों व उनकी उच्चतर आय पर क्रमबद्ध पुरोगामी रूप से वर्धित कर आधार को संकुचित करने वाला कहा जाता है, जिस कारण से उक्त सुझाव को एक सीमाकारी अभिलक्षण के रूप में इंगित किया जाता है, प्रभावतः यह क्रमबद्धता वांछित है और सर्वथा अपनाई जाती है। अतः, इस अर्थ में, यह सीमाकारी नहीं है। इसकी दृढ़ता यह है कि यह श्रम-आपूर्ति में विकृतियों समेत सभी व्यवहार्य कर-प्रणलियों पर विचार करता है।